**ग्राम पंचायत कटोरा, विकास खण्ड नगरोंटा सूरियां, जिला काँगड़ा के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017**

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.201 6 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत कटोरा, विकास खण्ड नगरोंटा सूरियां, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

1	श्रीमति अनुराधा	1-4-2014 से 22-1-2016
2	श्री कुलदीप सिंह	23-1-2016 से लगातार

सचिव :-

1	श्री संजीव कुमार	1-4-2014 से लगातार
---	------------------	--------------------

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत कटोरा के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	खाते तथा रोकड़ बही के अन्तशेष में भारी अन्तर	1.09
2	7	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.14
3	8	अनुदान का उपयोग न करना	23.12
4	9	प्राप्त अनुदानों की राशि से अधिक व्यय	0.06
5	10	बिना निविदाएँ प्राप्त किए निर्माण सामग्री का क्रय	2.44
6	11	Work Assessment के बिना भुगतान करना	2.88
7	12	मनरेगा के भुगतान वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	1.12

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत कटोरा, विकास खण्ड नगरोंटा सूरियां, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी व

श्री जीवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 3-1-2018 से 6-1-2018 तक ग्राम पंचायत कटोरा में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	3/2015	12/2014
2015-16	4/2015	9/2015
2016-17	2/2017	3/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत कटोरा, विकास खण्ड नगरोंटा सूरियां, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 21/2018 दिनांक 6-1-2018 द्वारा अनुरोध किया गया

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत कटोरा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) स्व स्रौत :- ग्राम पंचायत कटोरा के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	1192	298738	299930	176599	123331
2015-16	123331	115280	238611	161269	77342
2016-17	77342	451374	528716	256563	272153

(ii) अनुदान :- ग्राम पंचायत कटोरा के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	412973	879486	1292459	964490	327969
2015-16	327969	2286935	2614904	2152018	462886
2016-17	462886	4223963	4686849	2375158	2311691

5 रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹1.09 लाख का भारी अन्तर:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत कटोरा द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित्त बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना मे मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं की जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2017 को निम्नानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों में ₹109371.50 का अंतर था। अतः पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों से अतिशीघ्र मिलान कर के अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें।

1 रोकड़ बही खाता क पैरा 4(1)का अन्तशेष ₹272153

2 रोकड़ बही खाता ख पैरा 4(2) का अन्तशेष ₹2311691

योग ₹2583844

दिनांक 31-03-2017 को बैंक खातों में जमा अंत शेष का विवरण निम्नानुसार था।

क्र. सं	अनुदान का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1	KCCB Nagrota Surian	Own Sources	20027080250	212018.5
2	KCCB Nagrota Surian	MP Lads	50055874687	35932
3	KCCB Nagrota Surian	VKVNY	50052641656	888
4	KCCB Nagrota Surian	IAY	50052637912	0
5	KCCB Nagrota Surian	RAY/AAV	50052641555	192
6	KCCB Nagrota Surian	13th. F.C.	50055874654	3
7	KCCB Nagrota Surian	SDP.	50055950659	168
8	KCCB Nagrota Surian	N.C.	50055874542	183007
9	KCCB Nagrota Surian	TSC	50055874676	74274
10	KCCB Nagrota Surian	VMJSY	50059632859	11344
11	KCCB Nagrota Surian	3rd.STATE F.C.	50055981270	20035
12	KCCB Nagrota Surian	NRHM/Health	50056031135	2
13	KCCB Nagrota Surian	ADARSH NIRMAL GRAM YOJNA	50051293378	5
14	KCCB Nagrota Surian	14th. F.C.	50065412463	1936604
15	KCCB Nagrota Surian	MNREGA	20027080410	0
16	KCCB Nagrota Surian	MMAY	50065702140	0
		Total		₹2474472.5

अन्तर=₹2583844 – 2474472.50=₹109371.50

6 बजट प्राक्कलन का निर्धारित फार्म पर तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट

प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

7 पंचायत राजस्व की ₹0.14 की वसूली शेष:-

पंचायत सचिव कटोरा द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2017 तक पंचायत राजस्व (गृहकर) के रूप में निम्न विवरणानुसार ₹13540 की राशि वसूली हेतु जिसकी अतिशीघ्र वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

1 गृहकर :

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	6770	6770	13540	13540	0
2015-16	0	6770	6770	0	6770
2016-17	6770	6770	13540	0	13540

(2) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित्त बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फॉर्म 10 पर पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया। अतः गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

8 अनुदान ₹23.12 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹2311691 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

9 प्राप्त अनुदानों की राशि से ₹0.06 लाख का अधिक व्यय

सचिव ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाए गये आंकड़ो तथा वित्तीय स्थिती के अनुसार Adarsh Nirmal Gramin Yojna में दिनांक 31-03-2017 को ₹6325 ऋणात्मक दर्शाई गयी है जो कि किसी अन्य योजना के व्यय का लेखांकन Adarsh Nirmal Gramin Yojna में अथवा किसी अन्य योजना से Adarsh Nirmal Gramin Yojna का भुगतान करने के फलस्वरूप है। इस चूक का नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

10 बिना निविदाएँ प्राप्त किए ₹2.44 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय:-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72 (6) एवं अध्याय XI में पंचायत निर्माण कार्यों के लिए स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार

पंचायत द्वारा ₹244000 के स्टॉक/स्टोर का क्रय पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए किया गया, जिसे स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था। जाँच में यह भी पाया गया कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों में प्रयोग की गयी मदों का क्रय बिना निविदाएँ लिए किया गया था। अतः बिना निविदाओं के निर्माण सामग्री का क्रय करने बारे वस्तुस्थिति से स्पष्ट की जाए तथा सामग्री को भण्डार रजिस्टर में दर्ज करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

वा सं०	मास	मद का नाम	मात्रा (CUM/CUF)	दर (₹)	राशि (₹)
MPLAD					
16	9/2015	(i)रेत	6.8 m ³	700	4760
		(ii)बजरी	14.5 m ³	800	11600
		(iii)पत्थर	14.85 m ³	700	11880
		(iv)सीमेंट ढुलाई	-	-	1260
Adarsh Nirmal Gram Yojna					
6	9/2015	सोलर लाइट	10	19450	194500
7	9/2015	(i)रेत	6 m ³	700	4200
		(ii)बजरी	6 m ³	800	4800
		(iii)पत्थर तुडवाई	20 m ³	250	5000
		(vi) ढुलाई	-	400	400
		(v) पत्थर	8 m ³	700	5600
कुल योग					244000

11 Work Assessment के बिना ₹2.88 लाख का भुगतान करना :-

प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं पं० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या :एस एम् एस -17/2002- आर डी डी (जी आर एस) दिनांक 22-9-2009 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता की Work assessment के पश्चात ही पंचायत द्वारा भुगतान किया जाएगा, परन्तु जाँच में पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार पंचायत द्वारा ₹288244 का भुगतान Work assessment के बिना किया गया था। अतः इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टिकरण प्रस्तुत करते हुए Work assessment के बिना भुगतान पर अविलम्ब रोक लगाई जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

बा. सं.	मास	कार्य का नाम	राशि (₹)
VKVNY			
2	9/2015	रिटैनिंग वाल राकेश कुमार, कटोरा	18010
Sabha Nidhi			
29	12/2014	निर्माण रास्ता नाले से लेकर वट वृक्ष तक	3400
MGNREGA			
7	12/2015	निर्माण वाटर टैंक श्री नसीब सिंह	13860
10	12/2015	निर्माण एम्बुलेंस रोड लिंक रोड से हरिजन बस्ती तक	32340
11	12/2015	निर्माण वाटर टैंक श्री कश्मीर सिंह	26950

28	12/2015	निर्माण वाटर टैंक श्री कश्मीर सिंह	10044
131	2/2017	निर्माण वाटर टैंक श्री राकेश कुमार	11730
132	2/2017	निर्माण वाटर टैंक श्री मदन सिंह	18360
133	2/2017	निर्माण वाटर टैंक श्री पंकज कुमार	18360
134	2/2017	निर्माण वाटर टैंक श्री राजेश कुमार	18020
135	2/2017	निर्माण वाटर टैंक श्री श्याम लाल	18020
136	2/2017	निर्माण वाटर टैंक श्री सुभाष चन्द	20400
136/1	2/2017	निर्माण वाटर टैंक श्री सोम राज	14110
137	2/2017	निर्माण वाटर टैंक श्री मदन लाल	19890
138	2/2017	निर्माण वाटर टैंक श्री खुशी राम	10200
139	2/2017	निर्माण वाटर टैंक श्री राकेश कुमार	19550

Adarsh Nirman Gram Yojna

7	9/2015	निर्माण लिंक रोड से लेकर रुमेल सिंह के घर तक	15000
---	--------	--	-------

कुल योग

₹288244

12 मनरेगा के ₹1.12 लाख के भुगतान वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-

निम्नानुसार मनरेगा भुगतान वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए जिनके अभाव में किया गया भुगतान उचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर जांच हेतु उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा इसकी वसूली सम्बंधित से की जाए।

MGNREGA

बा. सं.	मास	कार्य का नाम	राशि (₹)
8	12/2014	निर्माण वाटर टैंक श्री स्वर्ण सिंह	21868
24	9/2015	निर्माण वाटर टैंक श्री यशपाल सिंह	18144
25	9/2015	निर्माण वाटर टैंक श्री प्रीतम चन्द	8910
26	9/2015	निर्माण वाटर टैंक श्री जोगिन्द्र सिंह	11664
27	9/2015	निर्माण वाटर टैंक श्री रतन चन्द	10854
28	9/2015	निर्माण वाटर टैंक श्री कश्मीर सिंह	10044
29	9/2015	निर्माण वाटर टैंक श्री स्वर्ण सिंह	16200
30	9/2015	निर्माण वाटर टैंक श्री भाग सिंह	14580

कुल योग

₹112264

13 नियमविरुद्ध एकाधिक रोकड़ बहियों का निर्माण करने बारे:-

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत पंचायत के समस्त लेनदेन को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किए जाने का प्रावधान है। परन्तु पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार वर्तमान में 15 अलग – अलग रोकड़ बहियों का अनुरक्षण किया गया है। अतः नियमों के विरुद्ध एक के स्थान पर अनुरक्षित इन 15 रोकड़ बहियों बारे उचित स्पष्टीकरण सहित भविष्य के लिए इन अतिरिक्त

रोकड़ बहियों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

14 प्राप्त अनुदान के लिए रसीदें जारी न करना:—

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (1 से 3) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को किसी भी स्रोत अथवा तरीके से प्राप्त आय/अनुदान के लिए इन नियमों में दिए गए प्रारूप-3 में रसीद जारी करनी आवश्यक है। परन्तु ग्राम पंचायत के लेखाओं की जांच में पाया गया कि अंकेक्षणवधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों विशेषतः आर. टी. जी. एस./ऑनलाइन बैंक प्राप्तियों के लिए किसी भी प्रकार की रसीद जारी नहीं की गई है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 मस्ट्रौल को जारी करने तथा उसके अभिलेखन व अनुरक्षण करने में प्रतिपादित नियमों की अवहेलना:—

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 102 (1 से 7) के प्रावधानों के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी द्वारा मुद्रित तथा प्रमाणित मस्ट्रौल ही पंचायत सचिव द्वारा सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी को किसी विकास/निर्माण कार्य में मजदूरों की हाज़िरी लगाने के लिए "मस्ट्रौल जारी करने के रजिस्टर" में प्रविष्टि के उपरान्त जारी किए जाएंगे। इन्ही नियमों में प्रावधित है कि इन मस्ट्रौल का अभिलेखन व अनुरक्षण हि.प्र. लोक निर्माण विभाग की कार्यपद्धति के आधार पर किया जाएगा। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा प्रयोग तथा भुगतान किए गए मस्ट्रौलों की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि उपरोक्त नियमों की अनुपालना आंशिक रूप में ही की गई है तथा मुख्य रूप से इन मस्ट्रौलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई:—

1 श्रम कानूनों के अन्तर्गत प्रावधान है कि प्रत्येक श्रमिक को छः दिन लगातार काम करने के पश्चात सातवें दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। परन्तु ग्राम पंचायत में इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा मनरेगा परियोजना के अन्तर्गत करवाए गए विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए जारी मस्ट्रौलों में मजदूरों द्वारा लगातार छः दिन से अधिक कार्य किए जाने के बावजूद भी उन्हें सवैतनिक अवकाश नहीं दिया गया है जो कि उपरोक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है।

2 मस्ट्रौल के भाग-3 जिसमें मजदूरों द्वारा किए गए कार्य का विस्तृत विवरण दर्ज किया जाता है को पंचायत द्वारा खाली रखा गया है जिस कारण मस्ट्रौल में किए गए कार्य तथा उसके विरुद्ध किए गए भुगतान को तकनीकी प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित किया जाना सम्भव नहीं हो सका है।

3 प्रयोग किए गए मस्ट्रौलों में मात्र कार्य का शीर्षक दर्ज किया गया है। मस्ट्रौल पर रखे गए मजदूरों से सम्बन्धित विकास/निर्माण कार्य में क्या अथवा किस प्रकार का काम करवाया

गया है का विस्तृत विवरण सम्बन्धित कॉलम में दर्ज नहीं किया गया है।

4 मस्ट्रौल को कनिश्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा न तो किए गए कार्य के लिए तकनीकी आधार पर सत्यापित नहीं किया गया है जिस कारण से भुगतान की गई राशि को किए गए कार्य को प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित नहीं किया जा सका है।

5 मस्ट्रौल में एक-दो को छोड़कर लगभग सभी प्रावधित कॉलम खाली छोड़ दिए गए हैं।

6 मस्ट्रौल जारी करने के रजिस्टर का अनुरक्षण तो किया गया है परन्तु इसमें भुगतान राशियों का ब्यौरा दर्ज नहीं है।

इस प्रकार से प्रावधित नियमों की अवहेलना तथा अनियमित भुगतान करना एक अति गम्भीर अनियमितता है जिसके बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इसमें सुधारात्मक कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियां:-

ग्राम पंचायत के लेखाओं की वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों तथा निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अन्य अभिलेख की अंकेक्षण जांच उपरान्त निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:-

1 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निश्पादन करने हेतु हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक एक अनुभागी/संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निश्पादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के "परिशिष्ट - ई" में दिए गए "अनुबन्ध" प्रारूप के अनुसार अनुबन्ध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निश्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निर्माण कार्यों का निश्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा है।

2 इन बिलों में किए गए कार्य की प्रमात्रा तथा खरीदी गई सामग्री का सत्यापन तकनीकी सहायक अथवा किसी भी अन्य जिम्मेदार पंचायत पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा नहीं किया गया है, जिस कारण किए गए भुगतान की प्रामाणिकता संदिग्ध हो जाती है। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा निश्पादित कार्यों में कनिश्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा किए गए कार्य का तकनीकी विवरण भी दर्ज नहीं किया गया है।

3 हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 103(4) की अनुपालना में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कोई भी लेखे तथा अभिलेख हि. प्र. लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार पर तैयार नहीं किए गए हैं जिस कारण पंचायत द्वारा किए

अथवा करवाए गए निर्माण कार्यों की अंकेक्षण जांच में दिक्कतें आई हैं। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4 तकनीकी सहायक द्वारा किसी भी निर्माण कार्य की पूर्णता की दिनांक तथा पूर्णता सम्बन्धी प्रमाणपत्र न तो मापन पुस्तिका में तथा न ही निर्माण कार्यों के रजिस्टर में दर्ज किए गए हैं। अभिलेख का यह अधूरा अनुरक्षण न केवल कार्यशैली में उदासीनता को प्रकट करता है बल्कि नियमविरुद्ध होने के कारण अनियमित भी है।

5 हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) तथा 105 में पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए निरीक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों के अनुसार किए गए कार्यों की जांच सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा की जानी अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत अभिलेख में ऐसी किसी भी जांच के प्रमाण अथवा प्रमाणपत्र नहीं पाए गए हैं। यह स्पष्टतयः सिद्ध करता है कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों की अवहेलना की जा रही है तथा इस कार्यप्रणाली में संदिग्धता दिखाई देती है। इस प्रकार नियमों की अवहेलना के सन्दर्भ में तथ्यपूरक स्पष्टीकरण सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त अब तक इस प्रकार से नियमविरुद्ध किए गए अनियमित निर्माण कार्यों को सक्षम उच्चाधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाए।

17 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना :-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उद्देश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं। चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

18 विहित रजिस्ट्रों का रख रखाव न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों / अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों / अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतितजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	मांग एवम् प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
5	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
6	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
7	खाता बहियाँ		29 (1)
8	मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर	-	-

19 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

20 लघु आपति विवरणिका:-इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

21 निष्कर्ष :- लेखाओं के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/-
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं० 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)171/2018 खण्ड-1-4582-4585 दिनांक 02.07.2018 शिमला-09
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत
- 1 सचिव, ग्राम पंचायत कटोरा, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
 - 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
 - 3 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
 - 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता/-
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं० 0177-2620881